Title: Regarding nationwide strike by coal workers.

12.20 hrs.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I wish to draw the attention of the Minister for Coal to a complete strike by more than five lakh of workers of Coal India and its subsidiaries since 3rd December. There is complete strike in ECL, CCL, BCCL, MCL, WCL, NCL and HCCL.

Sir, the coal workers have placed all their demands in the strike. All major trade unions, from Bharat Mazdoor Sangh to the Centre of Indian Trade Unions, have joined hands. Their demand is that the Bill which was introduced to allow private participation in the coal industry should be withdrawn. There is no need to allow private participation. Coal India and its subsidiaries are capable to produce as much coal as our country needs for power generation. There is no need for any private participation. Their demand is to converge all the subsidiaries into one company so that Coal India Limited can become viable. Three subsidiaries, namely, ECL, CCL and BCCL, are incurring losses and one-time grant should be sanctioned to these three subsidiaries.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already mentioned the matter.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, their demand is payment of arrears. One year back, wage revision of coal workers had been sanctioned but it has not been paid as yet. The Coal Minister is present here. I demand that he should respond to the demands of the five lakh coal workers so that their grievances would be redressed.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, a nation-wide strike of coal workers of coal India is going on from 3rd December till today. Five lakh workers have already joined the strike.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I allow you to associate because you have also given notice on the same issue.

SHRI SUNIL KHAN : Their demand is to withdraw the Coal Nationalisation (Amendment) Bill and that all the subsidiaries should be consolidated into one holding company. Arrears have not been received by the employees. Sir, I earnestly request the Minister to come out with a clear verdict that the Coal Nationalisation (Amendment) Bill would be withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bikash Chowdhury, you are allowed to associate in the matter.

...(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। दो नम्बर पर मेरा नोटिस है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am allowing only those Members who have given notices.

...(*Interruptions*)

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : कोल खदानों के मजदूर पिछली तीन तारीख से निजीकरण के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं।

वे निजीकरण के खिलाफ हैं। उनका वेज बोर्ड के साथ पिछले साल एक एग्रीमैंट हुआ था। उसके हिसाब से उनके एरियर्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है। â€¦ (व्यवधान) बहुत मीटिंग्स करने के बाद भी इसे नहीं किया गया। ऐसे में मजदूरों ने मजबूर होकर हड़ताल की। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मजदूर लोग लम्बी हड़ताल करेंगे। â€¦ (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया एवं उसकी आनुंगिक कम्पनियां सोमवार से हड़ताल पर हैं। तीन दिन की हड़ताल से सरकार को 60 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कर्मचारियों को दो प्रमुख मांगें हैं - एक तो उनके देय का भुगतान किया जाए और दूसरा कोल इंडिया का निजीकरण न हो। कोयला मंत्री बराबर यह कहते हैं कि उसका निजीकरण नहीं होगा लेकिन उनका "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो बयान आया है â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः बयान बताने की जरूरत नहीं है। आपको केन्द्र सरकार से क्या चाहिए?

श्री रामजीलाल सुमन **:** इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कोयला खदानों में बहुराट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि इसका निजीकरण नहीं होगा लेकिन दूसरी तरफ बहुराट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इससे यह मामला कंट्रोवर्शियल हो गया है। सरकार स्पट करें कि इसका निजीकरण नहीं होगा। कोयला कर्मचारियों का जो भुगतान शेा है, वह अविलम्ब किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, you have to speak about the strike and not about privatisation.

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख से कोल इंडिया एवं उनकी आनुंगिक कम्पनियों के 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस पर हम भी चिंता व्यक्त करते हैं। मंत्री महोदय का अखबारों में जो बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की छंटनी भी नहीं होगी और निजीकरण भी नहीं होगा लेकिन मंत्री जी का बयान आने के बाद भी हड़ताल जारी है। मंत्री जी ने निजीकरण नहीं करने की जो बात कही है और मल्टीनैशनल को खनन के क्षेत्र में आमंत्रित करने की जो बात कही है, उस बारे में वह सदन में स्पट करे। दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? बकाया राशि भुगतान करने के बारे में सरकार का क्या रूख है? â€¦ (व्यवधान) मल्टीनैशनल को खनन के क्षेत्र में आमंत्रण देने की बजाय विदेशी तकनीक को यहां लाया जाए जिससे कम लागत पर उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इसके साथ ही मैनजमैंट में व्याप्त भ्रटाचार को खत्म किया जाए। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Prabod Panda's speech.

...(*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I am raising the same issue. The coal mine workers are on strike all over the country. It started on 3rd December and it is still continuing to this date, that is 5th December, 2001. All the Trade Unions, like AITUC, CITU, BMS and HMS are supporting the strike.

Their first demand is the withdrawal of the Bill which paves the way for privatisation of coal mine sector. Their second demand is the full payment of arrears and restructuring of Coal India Limited. I think the Central Government will come forward and take some more steps so that lakhs and lakhs of coal mine workers are saved. This is what I wanted to say.

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जिस सवाल को उठाया, यह सही है कि तीन दिसम्बर से कोल इंडिया के अधिकांश कर्मचारीâ€¦ (व्यवधान) यह सही नहीं है हन्ड्रेड परसैंटâ€¦ (व्यवधान) प्राप्त जानकारी के मुताबिक 50 परसैंट â€¦ (व्यवधान)

Why are you arguing? It is 50 per cent. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sunil Khan, please hear him. I have allowed him to reply.

श्री राम विलास पासवान; अध्यक्ष जी, मंत्री मैं हूं और जवाब मैं ही दे रहा हूं। मेरे पास सूचना है। इनको कहां से इनफौर्मेशन मिल जाती है। उपाध्यक्ष जी, सिंगरौली में बिलकुल नार्मल काम हो रहा है लेकिन मैं उसके बारे में यह न कहकर कि कितने मजदूर हड़ताल पर हैं, मैं यही कहूंगा कि वे हड़ताल पर नहीं हैं। आप मेन डिमांड के बारे में सोचिये। बिलासपुर में 65 प्रतिशत लोग काम पर हैं। जहां तक मजदूरों का सवाल है, यह जग जाहिर है कि मैं मजदूरों के हित के लिये बदनाम हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : बदनाम नहीं, आपका सम्मान होगा।

श्री राम विलास पासवान; जो भी हो, कुछ लोग सम्मान भी करते हैं और कुछ लोग बधाई भी देते हैं। इसलिये जहां तक मजदूरों का सवाल है, कोयला खदान में काम करने वाले 60-70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। जितनी सहानुभूति आपको है, उतनी सहानुभूति मुझे भी है। मैंने जिस दिन से कोल मिनिस्टर का पदभार संभाला है, उस दिन घोाणा की थी कि कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा..

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे वापस लीजिये।

श्री राम विलास पासवान; दूसरी बात थी कि रिट्रेंचमेंट नहीं होगी। यहां पर माननीय सदस्य बैठे हुये हैं। स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी की बनी हुई है जिसमें यह बिल आया था और श्री बसुदेव आचार्य मैंम्बर हैं..

श्री बसुदेव आचार्य : हमने डिसैंटिंग नोट दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Please hear me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, let him complete.

श्री राम विलास पासवान; श्री संताेा मोहन देव उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। कमेटी ने ही सारी सिफारिशें भेजी हैं। जब यहां बिल रखा गया तो कहा गया कि मैं समर्थन करता हूं। इसलिये यहां बिल 2000 में पेश हुआ। सरकार ने उस अमेंडमेंट पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस बिल को इस सैशन में नहीं ला रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने कहा कि एश्योर कीजिये कि यह बिल इस सैशन में नहीं आयेगा, हड़ताल नहीं होगी। सबसे पहले हड़ताल कोल इंडिया में हुई है। मैंने अपील जारी की है कि यह बिल पार्लियामेंट में नहीं ला रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, do not make running commentaries now.

श्री राम विलास पासवान; हमारे यहां कुल मिलाकर 89 बिलियन टन प्रूब्ड कोल रिजर्व है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐस्टीमेटेड 400 बिलियन टन कोल का स्टॉक है जो 250 वार्षों तक कम होने वाला नहीं है । यह देश के लिये कितने शर्म की बात है कि हमारे पास 400 बिलियन टन कोयला होने के बावजूद हम 21

बिलियन टन कोयले का आयात कर रहे हैं। बिल में प्रावधान है कि प्राइवेट सैक्टर में कोयले का भंडार है। उनमें से उन्हें खनिज करने का अधिकार दिया जाये जिसका ट्रेड यूनियन्स विरोध कर रही हैं। सरकार की यह मान्यता है कि जब हमारे पास एक तरफ कोयले का इतना बड़ा भंडार है, दूसरी तरफ कोल इंडिया इस पोज़ीशन में नहीं कि वह खदान कर सके। उस प्रोडक्शन को उस लैवल तक ला सके जिसकी पॉवर सैक्टर को जरूरत है या भविय में जरूरत पड़ सकती है। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोल इंडिया के बाहर का जो ऐरिया है, उसमें खदान करने की अनुमति दी जाये जबकि इस बात के लिये ट्रेड यूनियन्स विरोध कर रही हैं। मेरे पास पिछली बार हुई बैठक के मिनट्स मौजूद हैं जिसमें कहा गया है;

> "The hon. Minister further re-assured that the Bill will not come up for discussion during the ongoing Session of Parliament. "

ट्रेड यूनियन्स के साथ बातचीत करने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी।

अभी मैं मिनिस्टर बना । उसके बाद नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठाया गया । 22 तारीख को उनके सामने ट्रेड यूनियन के सारे लीडर्स को बुलाया गया । उनसे बातचीत हुई और वहां सारी की सारी चीजें डिस्कस हुईं । हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एश्योर नहीं किया था कि वे संसद के सत्र में लायेंगे या नहीं लायेंगे, । लेकिन जब 25 तारीख को हमने ट्रेड यूनियन के लीडर्स के साथ बातचीत की तो मैंने कहा कि आपसे बातचीत हो रही है, जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी, यह बिल संसद में नहीं लाया जायेगा ।

आपने एरियर्स के संबंध में कहा, एरियर आज का बकाया नहीं है, यह काफी दिनों से बकाया चल रहा है । एरियर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है । अभी आपने कहा कि ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. में दो-तिहाई वर्क फोर्स है, दो-तिहाई खदानें हैं और एक-तिहाई प्रोडक्शन होता है । जहां एक-तिहाई माइन्स हैं । दूसरे डब्ल्यू.सी.एल. में एक-तिहाई खदान हैं और एक-तिहाई वर्क फोर्स है । वहां बहुमत है और हमें प्रोफिट है । हमारे पास 3100 करोड़ रुपये का एरियर था, उसमें से 350 करोड़ रुपये दे दिये गये, करीब 2700-2800 करोड़ रुपये हमारे पास बकाया है । हमारा पैसा पावर सैक्टर के ऊपर है, जो ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा है । प्राइवेट सैक्टर से बातचीत हो गई है । प्राइवेट सैक्टर के लोगों ने हमें पैसा देने का वायदा किया है कि हम मार्च तक पैसा दे देंगे । उस परिस्थिति में हमारे पास नौ सौ करोड़ रुपये हैं । नौ सौ करोड़ में हम चाहें तो जो हमारे पास मुनाफा कमाने वाली कम्पनीज हैं, हम उन्हें सौ परसेन्ट आज भी देने को तैयार हैं । लेकिन ट्रेड यूनियन के लोगों ने कहा कि आप सबके बीच में बंटवारा करो । हमने कहा ठीक है, सबके बीच में बंटवारे का मतलब है कि एक-तिहाई के हिसाब से बंटवारा हो ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो आज प्रोफिट कमाने वाली कम्पनीज हैं, ट्रेड यूनियन के लोग तैयार हो जाएं, हम उन्हें सौ परसेन्ट देने को तैयार हैं । इन्होंने कहा कि इसे तीन भाग में बांट दो । हमने कहा, ठीक है, हम एक-तिहाई करके देते हैं । उसके बाद हमने कहा कि स्क्रूटिनाइजेशन का पैसा मेरे पास मार्च तक आयेगा, उसके बाद हम बाकी पैसे का भुगतान कर देंगे । फिर कहा कि चलो एक-तिहाई नहीं, हम 40 परसेन्ट दिसम्बर तक करने को तैयार हैं । 40 परसेन्ट पैसा मार्च तक पे कर देंगे, जो पैसा बचेगा, उसे हम बाद में कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा यूनीफिकेशन का था । हमने कहा कि यूनीफिकेशन का मतलब क्या है । जब तीन कम्पनियां घाटे में चल रही हैं, इनका कहना है कि जो चार कम्पनीज मुनाफे में चल रही हैं, वे एक हजार करोड़ टैक्स के रूप में फाइनेन्स मिनिस्ट्री के पास जमा करते हैं, यदि यूनीफिकेशन हो जायेगा तो वह पैसा बच जायेगा । फाइनेन्स मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत हुई । उन्होंने कहा कि आप पैसा लेने के ज्यादा इच्छुक हैं या रिवाइवल के ज्यादा इच्छुक हैं । हमने कहा कि हम रिवाइवल चाहते हैं । उन्होंने कहा कि आप रिवाइवल पैकेज बनाकर दीजिए । हमने ट्रेड यूनियन के नेताओं से कहा कि आप रिवाइवल पैकेज बनाकर दीजिए । जब हमने कहा कि अभी बैठो तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग एरिया-वाइज बैठेंगे, उसके बाद सी.एम.डी. के साथ बैठेंगे, उसके बाद सैक्रेटरी के साथ बैठेंगे और फिर आपके साथ बैठेंगे । 15 जनवरी तक का पूरा खाका बन गया कि रिवाइवल पैकेज दे दीजिए, उसके मुताबिक हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे । उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि तीन कम्पनियां घाटे में चल रही हैं, चार कम्पनियां मुनाफे में चल रही हैं तो सबका पांव जोड़ दीजिए, फिर मुनाफे वाली कम्पनी है वह भी घाटे में चलनी शुरू हो जायेगी .

श्री बसुदेव आचार्य : यह स्टैंडिग कमेटी की रिकमेंडेशंस थीं ।

श्री राम विलास पासवान : एक तरफ कहते है कि स्टैंडिंग कमेटी मे नोट ऑफ डिसैन्ट हैं On the other hand, he is saying that it is the recommendation of the Standing Committee. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please hear him.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : What is the Minister saying? Do not mislead the House. ...(*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: If I am misleading the House... ...(*Interruptions*) Do not blame me. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, let him complete. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : My dissent is on private participation. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, there are number of people who have given notices. Do not give running commentaries.

...(*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : मैं कहना चाहता हूं कि इनकी तीन डिमान्ड्स हैं । उसमें एक यूनीफिकेशन का मामला है । हमने कहा रिवाइवल पैकेज दे दीजिए । आजकल हमें इस बात का दुख है कि सी.सी.एल. में प्रति दिन एक करोड़ रुपये का घाटा चल रहा था । जब से मैं मंत्री बना हूं, मैं मजदूरों के बीच में गया हैं । जितने कोयला मंत्री बने हैं उन्होंने इतनी कोयला खाने में विजिट नहीं की होगी । तीन महीनों के अंदर अंडरग्राउन्ड खानों से लेकर अन्य खदानों में मैंने विजिट करने का काम किया है । हम मजदूरों की पीठ ठोंकने का काम कर रहे हैं । मजदूर काम करने को तैयार हैं । ट्रेड यूनियन का मतलब यूनियन होता है, ट्रेड नहीं होता है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि सारी बातचीत हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लोग तैयार नहीं हैं । इस बीच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटक के लोग तैयार नहीं थे ।

उन्होंने कहा कि मजदूरों के हित के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जब इनसे हमारी बातचीत हो गई, एक तरफ घाटे में चल रहा है, सरकार की पॉलिसी आप जानते हैं कि सरकार कतना घाटा उठाएगी? एक साल 400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, दूसरे साल 900 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और तीसरे साल 2600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। कल यदि आप लोग मंत्री बनेंगे, हम तो उधर भी रहे हैं और इधर भी रहे हैं, यदि कल 3200 करडो रुपये का घाटा होगा तो कौन इसको सहन करेगा? आपको कोशिश करनी चाहिए। आखिर ट्रेड यूनियन्स के लोग सिंगरौली में भी तो हैं, ट्रेड यूनियन एन.सी.एल. में भी है, डब्लू.सी.एल. में भी है। वहाँ ट्रेड यूनियन के लोग जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और जब हम बार-बार कह रहे हैं कि आप पहले रिवाइवल कीजिए और हमें इस बात की खुशी हुई कि वहां जो एक करोड़ रुपये का घाटा प्रतिदिन चल रहा था, वह घटकर 50 लाख रुपये पर पहुंच गया। सी.सी.एल. में हम मार्च तक मुनाफा कमाने की स्थिति में आने वाले हैं। लेकिन जहां हम मुनाफा कमाने की स्थिति में आने वाले हैं, वहां वे लोग मिलकर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ को तहस-नहस करना चाहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? â€¦ (व्यवधान) हम अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सेन्सिबल आदमी इस तरह की बात का समर्थन नहीं कर सकता और इसलिए हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। â€¦ (व्यवधान)